

पेषक

हरिओम,  
संयुक्त संघिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

संक्षेप में

निदेशक  
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई  
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड  
देहरादून।

## आधीरिक विकास अनुभाग—२

देहरादून: दिनांक: २८ मई, २००९

**विषय:** वित्तीय वर्ष २००९-१० हेतु खनन प्रशासन का अधिकान, आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

मम पर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: १३४/लेखा/आयोजनागत/२००९-१० दिनांक २४.४.२००९ तथा शासनादेश संख्या: २०५/XXVII(1)/२००९ दिनांक २५ मार्च २००९ के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष २००९-१० में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हेतु ०३-खनन प्रशासन का अधिकान के अन्तर्गत अवधारणाद्वारा मदों में निम्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष २००९-१० हेतु कुल रूपये ७.३३ लाख (रु० सात लाख तीन सौ हजार मात्र) की धनराशि के बाय किये जाने हेतु आपके निवारन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

कोड/मद का नाम	आवंटित बजट (रु० हजार में)
०४—यात्रा व्यय	१५०
०५—स्थानान्तरण यात्रा व्यय	३३
११—लैखन सामग्री और कार्मों की छपाई	६७
१२—कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	३३
१५—व्यावरायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	१००
१८—इकाईन	११७
२९—अनुरक्षण	६७
४४—प्रशिक्षण	३३
४५—अवकाश यात्रा व्यय	३३
४६—कम्प्यूटर हार्ड वेयर/सरफटवेयर का कर्य	३३
४७—कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तदसंबंधी स्टेशनरी का कर्य	६७
कुल योगः	७३३
(रु० सात लाख तीन सौ हजार मात्र)	

२— वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर दो०८-०८ के प्रथम पर रखा जायेगा, और धूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की ५ तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनेजर की अध्याय-१३ के प्रत्तर-११६ की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा तथा प्रत्तर-१२८ की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की २५ तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। यदि नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के दिल्ली अनुशासनात्मक (गा० मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव)

कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर की अवगत करा दिया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर-130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3— उक्त धनराशि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार अवचनबद्ध मदों में ही स्वीकृत की जा रही है व आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि अवचनबद्ध मदों में धनराशि के व्यय करते समय मितव्ययता का दिशेव ध्यान रखा जाय, तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कदाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4— व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मनुअल/प्रिलीय हस्तापुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता है। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गयी धनराशि का नासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5— अवचनबद्ध मदों में बजट आवंटन की सीमा में ही व्यय को सीमित रखा जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2010 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

6— व्यय करते समय यथा आवश्यक उत्तराखण्ड अधिग्राहि नियमावली 2008 के प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।

7— उपकरण/फर्नीचर आदि का क्रय डी०जी०एस०एण्ड ३० की दरों पर अथवा टैण्डर/कुटैशन के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

8— कम्प्यूटर आदि का क्रय एन०आई०सी०/आई०टी० विभाग वी संसुन्ति से अथवा उनके दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

9— उक्त व्यय बालू वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु अनुदान संख्या-23 के मुख्य लेखाशीर्षक 2853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 02-खानों का विनियमन तथा विकास, आयोजनेतार 001-निदेशन तथा प्रशासन (लघु शीर्षक 003 के स्थान पर), 03-खनन प्रशासन का अधिकान-00, मद अन्तर्गत प्रस्तर-1 में उल्लिखित प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

10— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 74/XXVII(1)/2009 दिनांक 18 मई 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरिओम)  
संयुक्त सचिव।

**पुष्टीकन संख्या: 978/VII-II-09/50-ख/2006 तदनिर्दित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव-मा० मुख्यमन्त्री जी।
3. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोशाधिकारी/कोशाधिकारी, देहरादून।
5. उप निदेशक/नोडल अधिकारी बजट, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिओम)  
संयुक्त सचिव।